vkj- ,u- vkbZ- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- la[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 14 vad % 23 y[kuÅ] xq:okj 21 flrEcj 2023 ls 27 flrEcj 2023 rd i`"B&8 eY; % ,d :i;k

मुख्यमंत्री ने की सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों की समीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के प्रयासों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। राज्य सरकार की ओर से यहां जारी एक बयान के अनुसार, बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीजी मुख्य रूप से अंग्रेजी के फाइव पी (पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्लैनेट) के सिद्धांत पर आधारित हैं और सरकार वर्ष २०३० तक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने एसडीजी के ढांचे के तहत चिन्हित क्षेत्रों में राज्य द्वारा की गई प्रगति पर संतोष जाहिर किया। आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य ने एसडीजी में शामिल एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी गरीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में रिक र्ड ३.४३ करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाया है। राज्य सरकार वर्ष २०२४ तक हर घर में नल का

पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए २०१८ से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना लागू की गई है, और इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य की वास्तविक प्रगति का डेटा केंद्र और नीति आयोग के विभिन्न मंत्रालयों के साथ साझा किया जाना चाहिए और एसडीजी एजेंडा—२०३० में शामिल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा नियमित निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सुधार करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि भूजल दोहन को कम करते हुए भूजल रिचार्ज को बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा मिशन मोड में कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में १५ वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का स्कूलों में शत—प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाये और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लेकिन सभी वर्गों एवं क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।

ऑफिसर डेस्क प्रणाली से सचिवालय के कार्यों को नयी रफ्तार देगी योगी सरकार, पहले चरण में २० विभागों में लागू की जाएगी प्रणाली

लखनऊ। योगी सरकार ने सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने, समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता के लिए विभागों में सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इससे जहां फाइलों का तेज निस्तारण होगा, वहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को बिना देरी के लागू किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। मालूम हो कि मोदी सरकार के ४० मंत्रालयों में ६२३ डेस्क इकाई स्थापित की गयी है। डेस्क ऑफिसर प्रणाली के तहत एक अनु सचिव या वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी डेस्क से जुड़ी जिम्मेदारियों की प्रेंति के आधार पर डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। योगी सरकार द्वारा सचिवालय में लागू की जा रही डेस्क ऑफिसर प्रणाली का उद्देश्य सचिवालय स्तर पर विभागों में नियामक कार्यों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण करना है। यह प्रणाली ऑफिसर ओरिएंटेड है। इसके जरिये सचिवालय स्तर पर स्थित विभागों में अनुभागों के माध्यम से उच्चाधिकारियों तक पत्रावली प्रस्तुतिकरण के दौरान

त्वरित कार्य निस्तारण में विलम्ब की संभावना को समाप्त करना है। ऐसे में सचिवालय स्तर पर विभागों में नियामक कार्यों (रेग्युलेटरी वर्क) के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए सचिवालय स्तर पर स्थित विभागों में एक—एक डेस्क इकाई गठित की जाएगी। इसके लिए विभागों से सुझाव मांगे गये थे। इस पर सचिवालय के बीस विभागों द्वारा अपने विभाग में डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करने पर सहमति दी गयी, जहां पर इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। सचिवालय स्तर के विभाग में डेस्क ऑफिसर प्रणाली के तहत हर डेस्क इकाई में १ विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निजी सचिव और अपर निजी सचिव की तैनाती की जाएगी। विभिन्न विभागों में कुछ ऐसे कार्य होंगे जो निश्चित रूप से नियामक कार्य (रेग्युलेटरी वर्क) होंगे। ऐसे में डेस्क अ फिसर प्रणाली लागू करने के लिए सबसे पहले विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों को सामान्य (रुटीन) एवं नियामक कार्यों (रेग्युलेटरी वर्क) में विभाजित करना होगा। इसको लेकर सचिवालय के कई विभागों ने सहमति दे दी है। वहीं पहले चरण में सचिवालय के २० विभागों में डेस्क इकाई का गठन कर डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया

नई दिल्ली। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले साल २६ जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को

मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राजदूत ने कहा कि मोदी ने आठ सितंबर को दिल्ली में जी२० शिखर सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह निमंत्रण दिया था। यह पूछे जाने पर कि क्या गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है, गार्सेटी ने इसकी पुष्टि नहीं की। एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत से उन रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि क्या भारत गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए क्वाड देशों के नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। इस पर गार्सेटी ने कहा कि जी२० शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया है। यदि बाइडन निमंत्रण स्वीकार करते हैं, तो वह बराक ओबामा के बाद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने वाले वह दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। ओबामा ने २०१५ में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी। हाल में जी२० शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए बाइडन की राष्ट्रपति बनने के बाद इस देश की यह पहली यात्रा थी। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल—सिसी मुख्य अतिथि थे।

डेंगू से घबराएं नहीं, अलर्ट पर सभी अस्पताल, दवा भी उपलब्ध : ब्रजेश पाठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर लोगों से अपील की है। बुधवार को डिप्टी सीएम ने कहा कि डेंगू को लेकर कोई चिंताजनक बात नहीं है। हम सभी लगातार निगरानी कर रहे हैं और प्रदेश के सभी अस्पतालों और चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क दवाएं उपलब्ध है और डेंगू से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मौसम बदलने की वजह से भी लोगों में वायरल बुखार आ रहे हैं। ऐसे में अगर लक्षण दिखाई देते है तभी डेंगू की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि हर बुखार डेंगू नहीं है। हमारी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठक हो रही है। हर स्तर पर डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि लोग कहीं पर भी पानी न जमा होने दें। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास और नगर निगम लगातार मिलकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही एंटीलार्वा स्प्रे, फ गिंग और डेंगू से बचाव के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

संजय गांधी अस्पताल का निरस्त पंजीकरण बहाल किया जाए : कांग्रेस

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस ने रायबरेली स्थित संजय गांधी अस्पताल का निरस्त किया गया पंजीकरण बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा। पत्र में स्थानीय नागरिकों की असुविधाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अस्पताल दशकों से स्थानीय और आस—पास के जिलों के नागरिकों को न्यूनतम शुल्क पर बिना लाभ के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है।

सम्पादकीय

कनाडा को करारा जवाब

कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों के कारण भारत तथा कनाडा के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। भारत ने खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार संभवतरू भारत से जुड़े होने के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया। वास्तव में कनाडा में हिंसा के किसी भी ्त्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और स्वार्थ से प्रेरित हैं। ये आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश हैं जो कनाडा में आश्रय पा रहे हैं और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले को लेकर एक भारतीय अधिकारी को कनाडा द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को भारत से निष्कासित कर करारा जवाब दिया गया है। भारत ने जुलाई में भी कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया था और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर आपत्ति जताने वाला पत्र जारी किया था। गौरतलब है कि दिल्ली में आयोजित जी२० शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष ट्रूडो के बीच १० सितंबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो को कनाडा में चरमपंथी तत्वों द्वारा जारी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था क्योंकि ये तत्व अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं तथा वहां भारतीय समुदाय को डरा रहे हैं। इसके बाद ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में कहा था कि कनाडा की विभिन्न सुरक्षा एजेंसी कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच संभावित संबंधों के पुख्ता आरोपों की जांच कर रही है। हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अन्य अवैध गतिविधियों के लिए कनाडा में जगह मुहैया कराया जाना कोई नई बात नहीं है। पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सिख संगठन सिख फ र जस्टिस और खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था।

२२ सितम्बर से ज्ञान कुम्भ की होगी शुरुआत, डिप्टी सीएम करेंगे उद्घाटन

लखनऊ। आगामी २२ सितम्बर से राजधानी में ज्ञान कुम्भ की थीम पर राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है। यह आयोजन केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स संयुक्त रूप से बलरामपुर गार्डन में करने जा रहे हैं। शुक्रवार २२ सितम्बर को शाम ५ बजे पुस्तक मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। पूर्वाह्न ११ बजे से रात ६ बजे तक चलने वाले इस ११ दिवसीय पुस्तक मेले के बारे में संयोजक मनोज सिंह चंदेल ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह बताया कि इस वर्ष यह हमारा २०वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। लखनऊ के इस पुस्तक मेले ने देश के शीर्ष १० पुस्तक मेलों में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने बताया कि इस मेले में दिल्ली, मुंबई, रायपुर, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, रायपुर, गुजरात और राजस्थान के प्रकाशक अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा की पुस्तकों के साथ आ रहे हैं। पुस्तक मेले में पुस्तक विमोचन, लेखकों से मिलें, कवि सम्मेलन, मुशायरा, युवा और बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सह आयोजक आकर्षण जैन ने बताया कि हमेशा की तरह यह मेला निःशुल्क रहेगा और पुस्तक प्रेमियों को न्यूनतम १० प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने आभासी दुनिया में किताबों के कभी न खत्म होने वाले फायदों के बारे में भी बात की। मेले के निदेशक आकर्ष चंदेल ने बताया कि प्रमुख प्रकाशकों के हजारों शीर्षकों के प्रदर्शन के लिए १५ हजार वर्ग फीट का वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर लगाया गया है। पुस्तक प्रेमियों की सुरक्षित और आरामदायक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गये हैं। आकर्षण ने बताया कि मेले में राजकमल, वाणी–भारतीय ज्ञानपीठ, राजपाल लोकभारती, प्रभात प्रकाशन, हिंद युग्म, सामायिक, सेतु, सम्यक, प्रकाशन संस्थान, प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग, हिंदी संस्थान आदि के स्टाल प्रमुख होंगे। इसके साथ ही जनगणना निदेशालय यूपी, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, उर्दू अकादमी दिल्ली, सस्ता साहित्य मंडल, गायत्री ज्ञान मंदिर, वैदिक साहित्य, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, रामपुर रजा लाइब्रेरी पब्लिशर्स, तिरुमाला, यशिका, एंजेल और कई अन्य प्रकाशक और वितरक भाग ले रहे हैं।

मोटो जीपी के जरिए दुनिया के २०० देशों में 'ब्रांड यूपी' को प्रमोट करेगी योगी सरकार

लखनऊ। भारत के ग्रोथ इंजन बनने के लिए प्रयासरत उत्तर प्रदेश अब मोटो जीपी भारत २०२३ के आयोजन के जरिए वैश्विक पटल पर अपनी छवि को और अधिक मजबूती प्रदान करने जा रहा है। योगी सरकार २२ से २४ सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इस वैश्विक ख्याति प्राप्त इवेंट में अपनी सहभागिता दर्ज कराने जा रही है। इस इवेंट के सफल आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश को दुनिया के २०० से अधिक देशों में बतौर श्ब्रांड यूपीश स्थापित करने का मौका मिलेगा। इस आयोजन से रेसिंग स्पोर्ट्स समेत तमाम स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए भी भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा। वहीं, दुनियाभर की नामी कंपनियों के बीच उत्तर प्रदेश की छवि एक ब्रांड के तौर पर उभरेगी, जिससे योगी सरकार के वन ट्रिलियन ड लर की इक नमी के संकल्प की पूर्ति होगी। पूरे आयोजन में योगी सरकार की सहभागिता का रोडमैप उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी द्वारा तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष १० से १२ फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट २०२३ के सफल आयोजन के जरिए ३७ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रदेश में निवेश आया था। इसमें दुनिया की सभी प्रमुख कंपनियों की भी व्यापक उपस्थिति थी। अब प्रदेश में मोटो जीपी के आयोजन के दौरान भी स्पोर्टिंग वर्ल्ड समेत दुनिया की लीडिंग मल्टीनेशनल ब्रांड्स की प्रदेश में उपस्थिति रहेगी। इस मौके को प्रदेश में निवेश को गति देने के अवसर के तौर भुनाने के

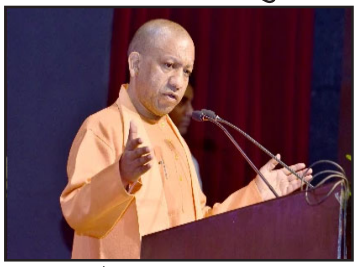

लिए भी योगी सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इस इवेंट में रेडबुल, शेल, बी–विन, बीएमडब्ल्यू, ओकले, मॉन्सटर, मोटुल, टिसॉट, रेपसॉल, पोलिनी, गो प्रो, ह न्डा, मिशेलिन, एमेज न, डीएचएल व पेट्रोनॉस जैसी २७५ दिग्गज कंपनियां भाग ले रही हैं। इन कंपनियों के सीईओ भी इवेंट में शिरकत करने आ रहे हैं, ऐसे में योगी सरकार की प्राथमिकता इन कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करने पर है। बैठकों के जरिए प्रदेश में अगर इन कंपनियों के निवेश का रास्ता साफ हो गया तो इससे ब्रांड यूपी की वैश्विक स्वीकार्यता में बड़ी बढ़ोत्तरी होगी। इस ग्लोबल रेसिंग इवेंट में कुल मिलाकर प्रति दिन १.५ लाख के करीब लोग प्रतिभाग करेंगे। वहीं, विदेशों से १०००० लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आएंगे। इसके अतिरिक्त, २०० देशों में इस इवेंट को टेलीकास्ट किया जाएगा और ८०० से लेकर १.८० लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में इवेंट से जुड़े टिकट्स बिक रहे हैं। कुल २० अलग–अलग रेसिंग इवेंट्स का आयोजन इन तीन दिनों में होगा जिसमें मेन स्पोर्टिंग इवेंट के तहत फाइल रेस २४ सितंबर को होगी। इसमें मुख्यतः ११ टीमें हिस्सा ले रही हैं और दुनिया के सभी देशों से रेसिंग इवेंट के शौकीन दर्शक ग्रेटर नोएडा का रुख कर रहे हैं। यह आयोजन कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक आंकलन के अनुसार, इस इवेंट की टेलीकास्टिंग को पूरी दुनिया में ४५ करोड़ से अधिक व्यूअरशिप मिलेगी। जाहिर सी बात है, इतने बड़े अवसर को योगी सरकार केवल एक आयोजन तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। मोटो जीपी रेसिंग इवेंट में निवेश, पर्यटन, उद्योग समेत व्यापारिक दृष्टिकोण से छुपी सभी संभावनाओं को तलाश को योगी सरकार पूरी प्रमुखता दे रही है। यही कारण है कि मोटो जीपी के कवर्स में ताज महल और वाराणसी के घाट फोकस में दिख रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त पर्यटन उद्योग तेजी से गति पकड़ चुका है और विदेशों से लोग अब केवल ताज महल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम विरासतों का साक्षी बनने आते हैं। इसी कारण से मोटो जीपी के आयोजन के जरिए प्रदेश में तमाम संभावनाओं को तलाशने और उसे गति देने पर भी फोकस किया जा रहा है।

महिला आरक्षण सम्बन्धी बिल को लेकर बोलीं मायावती कहा–आरक्षण के नाम पर आंखों में धूल झोंक रही सरकार

लखनऊ। राजधानी में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनगणना, परिसीमन और दूसरी कई खामियों के साथ संसद में दिखावे के लिए महिला आरक्षण सम्बन्धी बिल पेश करना देश की करोड़ों महिलाओं की आंखों में धूल झोंकना है। मायावती ने कहा कि संसद से बिल भले ही पारित हो जाए लेकिन कई वर्षों तक नई जनगणना होने में और उसके बाद कई वर्षों तक परिसीमन होने से ये बिल महिलाओं को त्वरित लाभ नहीं दे रहा है। साथ ही इस बिल में एससी–एसटी महिलाओं के लिए उन्होंने लागू आरक्षण के अतिरिक्त आरक्षण देने की मांग भी की। मायावती ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं के वोट के लिए इस प्रकार के बिल को पास कराया जा रहा है। मायावती ने कहा कि बिल पेश किये जाने और उसको लागू करने में सरकार की नियत साफ नहीं है। मायावती ने कहा कि एससी–एसटी के अतिरिक्त

ओबीसी महिलाएं भी सामान्य वर्ग की महिलाओं से काफी पीछे हैं। ऐसे में उनके लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी बीजेपी के साथ आ गई हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि उनका महिलाओं के आरक्षण से कोई नहीं बल्कि आगामी चुनावों में उन्हें बहलाकर उनका वोट लेने से लगाव है। मायावती ने कहा कि सर्व समाज के आगे देश की महिलाओं को जो अधिकार अभी तक मिले हैं वो हिन्दू कोड बिल के माध्यम से मिले हैं और इन्हें देने के पीछे बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का हाथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के सन्दर्भ में पारित होने वाले बिल में पहले भी अड़ंगा लगाया था। जिसके बाद उसे टुकड़ों में पास किया गया। मायावादी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि संसद में पेश महिला आरक्षण बिल में से दो प्रावधानों को निकाला जाये अथवा बिल महिलाओं को लाभ दे सके इसकी त्वरित व्यवस्था की जाये। मायावती ने कहा कि चूँकि इस बिल का सीधा असर देश की करोड़ों महिलाओं के उत्थान पर होगा इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ।

विधानसभा प्राक्कलन समिति ने समीक्षा कर दिए निर्देश

लखनऊ। दैवीय आपदा, वरासत, बाढ़ ग्रसित समस्याएं व दाखिल खारिज के मामलों का निस्तारण आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार कर किया जाए और पूर्ण विवरण के साथ रिपोर्ट दी जाए। यह निर्देश मंगलवार को विकास भवन में आयोजित विधानसभा प्राक्कलन समिति की बैठक में दिए गए। जिसका समिति ने अध्यन किया और निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के दैवीय आपदा, तहसीलों में वरासत, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की समस्याएं व दाखिल खारिज के मामलों का निस्तारण संबंधित आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करते हए करें और पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। बैठक में सदस्य, जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. शुभि सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर समेत सभी अधिकारी रहे। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने समिति को १७४ न्याय पंचायत व ४६१ ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्मित

शौचालय, पंचायत भवन व अंत्येष्टि स्थलों का वर्षवार विवरण दिया। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, संचारी रोग नियंत्रण एवं आयुष्मान कार्ड योजना की समीक्षा की, जिसका पूरा विवरण मांगा। साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को पांच वर्ष से अधिक समय से चल पूर्ण करने के निर्देश दिए। समिति के सदस्यों ने महानगर सचिवालय कॉलोनी व सृजन विहार क्षेत्र में जलभराव व टूटी सड़कों का निर्माण कराने की बात रखी। जिसे सभापति ने सहायक नगर आयुक्त को समस्याक का समाधान कराने के निर्देश दिए। वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित २४ किराना दुकानों की नियमित समीक्षा कराने के साथ बंद दुकानें या बन्द होने की स्थिति में भी समीक्षा नियमित समीक्षा कराने को कहा। मंगलवार को उप्र विधानसभा प्राक्कलन समिति वर्ष २०२२–२३ की द्वितीय उपसमिति जिले के भ्रमण पर रही। सभापति लोकेन्द्र प्रताप सिंह ने विकास भवन सभाकक्ष में सदस्यों व अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उपसमिति के सामने जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने राजस्व विभाग के कार्यों की बुकलेट रखी।

अखिलेश यादव ने विधेयक को बताया 'आधा अधूरा', लिखा–भाजपा ने महाझूठ से शुरू की पारी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सवाल उठाते हुए इसे आधा–अधूरा विधेयक करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर लिखा, ''नयी संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने 'महाझूठ' से अपनी पारी शुरू की है। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी।'' उन्होंने कहा, ''भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है न जातिगत गणना के, इनके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। ये आधा–अधूरा विधेयक 'महिला आरक्षण' जैसे गंभीर विषय का उपहास है, इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनावों में भाजपा के विरुद्ध वोट डालकर देंगी।'' सरकार ने

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद के निचले सदन में पेश किया। इसे 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' कहा गया है।

वादों को छुपाने के लिए नए तमाशे करती है भाजपा : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने विकास के दावे तो बहुत

किए पर जमीन पर उसकी कहीं छाया तक नहीं दिखाई देती है। भाजपा का एजेन्डा जनता के हितों और समस्याओं से सम्बन्धित नहीं होता है। जनहित में कोई कदम उठाने के बजाय भाजपा अपने पुराने वादों और अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए नए तमाशे और इवेंट करती रहती है ताकि जनता उनकी चकाचौंध में बहकी रहे। सपा प्रमुख ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार की कुनीतियों के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। बीते पांच साल में ४७ प्रतिशत भारतीयों ने अपनी जीवन बीमा प लिसी या तो सरेंडर की या फिर उसे रिन्यू नहीं कराया है। लोगों के पास बीमा कवर घटता जा रहा है। ६४ प्रतिशत लोगों के पास या तो कोई बीमा नहीं है या वह अपर्याप्त है। यही स्थिति किसान फसल बीमा योजना की भी है।

धनशोधन अधिनियम मामले में यादव सिंह के चार्टर्ड अकाउंटेंट की याचिका खारिज

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े मामले में नोएडा के तत्कालीन मुख्य अभियंता यादव सिंह के चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन लाल राठी की याचिका खारिज कर दी है। राठी बाद में इस मामले में यादव सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा, ''किसी अनुसूचित अपराध के मामले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा ३०६ के तहत दी गई माफी किसी व्यक्ति को पीएमएलए के तहत अपराध में बरी करने का आधार नहीं होगी, जब तक कि निश्चित रूप से, आरोपी व्यक्ति पीएमएलए के तहत मामले में पूरी तरह से पूर्ण और सही खुलासा करके माफी नहीं मांगता।'' पीठ ने राठी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उसने पीएमएलए के तहत गठित विशेष अदालत में चल रहे पीएमएलए मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में इस बात पर जोर दिया था कि वह करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मुख्य मामले में, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के बाद विशेष अदालत द्वारा सुने जा रहे पीएमएलए के मामले में मुख्य आरोपी यादव सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया था। लिहाजा अदालत ने उसे माफी दे दी थी इसलिए उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता कुलदीप श्रीवास्तव ने राठी की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पीएमएलए मामला आय से अधिक संपत्ति मामले से अलग है और इस तरह, राठी को पीएमएलए मामले में खुद–ब–खुद राहत नहीं मिलेगी। श्रीवास्तव ने कहा, 'अगर याचिकाकर्ता आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकारी गवाह बनने के आधार पर राहत चाहता है, तो वह सह–अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विस्तृत खुलासा करने के लिए विशेष अदालत (प्रवर्तन निदेशालय) का रुख कर सकता है।' सीबीआई ने ३० जुलाई, २०१५ को नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य अभियंता यादव सिंह, उसकी पत्नी कुसुमलता, बेटियों गरिमा भूषण और करुणा सिंह, बेटे सनी सिंह, बहू श्रेष्ठा सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन लाल राठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। यादव सिंह ने २००४ से २०१५ के बीच नोएडा प्राधिकरण में अपनी तैनाती के दौरान कथित तौर पर २३ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। इस अवधि के दौरान उसके द्वारा अर्जित संपत्ति कथित तौर पर उसकी आय के ज्ञात स्रोत से ५१२ प्रतिशत अधिक थी।

खाली कराये जा रहे जर्जर मकान, अभी तोड़ने के निर्देश नहीं

लखनऊ। आलमबाग क्षेत्र के आनंदनगर स्थित रेलवे क लोनी के जर्जर मकानों में रह रहे एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन भले ही सजग हो गया है, लेकिन यहां खाली पड़े जर्जर मकानों में बाहरी लोगों ने भी डेरा डाल रखा है। अधिकारियों ने निरीक्षण में इन्हें यहां जमा पाया तो अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यहां रहने वाले बाहरी लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं। कोई रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रहा है तो कोई अन्य कोई कार्य। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के मुताबिक यहां करीब ५०० से ज्यादा मकान जर्जर स्थिति में हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जो बाहरी लोग यहां रह रहे हैं, इनको कोई विभागीय परमिशन नहीं थी, लेकिन अब चेतावनी दे दी गई है कि वह यहां से चले जाएं। इंजीनियरिंग विभाग के मुताबिक आरडीएसओ के पास शांतिपुरम क लोनी से मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू किया जाना है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये है कि कई मकान ऐसे

भी हैं जो जर्जर स्थिति में नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ शुरू करने से पहले इन मकानों को भी खाली कराना होगा नहीं तो कार्रवाई में दिक्कत हो सकती है। हालांकि ६८० मकान गिराए जाने की तैयारी है। रेखा श्रीवास्तव, सीनियर डीसीएम उत्तर रेलवे ने बताया कि मकानों को खाली कराया जा रहा है लेकिन अभी उन्हें तोड़ने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

बिना मानचित्र ओसियन सिटी का निर्माण सील

लखनऊ। जिला पंचायत ने क्षेत्र में हो रहे नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस व प्रशासन के साथ तीन जगह अभियान चलाकर एक क लोनी का निर्माण सील कर दिया। जिसका मानचित्र स्वींत नहीं कराया गया था। मंगलवार को मोहनलालगंज क्षेत्र में जिला पंचायत अंतर्गत विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान सुल्तानपुर रोड पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ज्योति कुमार दीक्षित, एसडीएम हनुमान प्रसाद संबंधित थाने की फोर्स के साथ पहुंचे। तीन जगहों पर किया जा रहा क लोनी निर्माण देखा, जिसका बिल्डरों से मानचित्र मांगा। इसमें वैस्टन व सरकार सिटी के नाम से विकसित की जा रही क लोनी का मानचित्र स्वींत मिला और निर्माण भी मानचित्र के अनुसार बताया। जबकि ओसियन सिटी का मानचित्र स्वींत न होने पर किया गया निर्माण सील कर दिया। जहां नींव, बाउंड्रीवाल, सड़क, पोल, नाली, साइट ऑफिस आदि निर्माण कराया गया था। बिल्डर को दोबारा निर्माण करने पर एफआईआर की चेतावनी दी।

बिलकीस बानो मामला : न्यायालय ने पूछा कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार?

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने २००२ के गुजरात दंगों के दौरान बिलकीस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में ११ दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने ११ दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील से पूछा, ''क्या माफी मांगने का अधिकार (दोषियों का) मौलिक अधिकार है। क्या कोई याचिका संविधान के अनुच्छेद ३२ (जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंचने के अधिकारसंबंधित है) के तहत दायर की जाएगी। वकील ने जवाब दिया, नहीं, यह दोषियों का मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित और अन्य को भी अनुच्छेद ३२ के तहत याचिका दायर करके सीधे शीर्ष अदालत में पहुंचने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस बीच, एक दोषी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वरिष्ठ वकील ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत उच्च न्यायालयों के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है। संविधान के अनुच्छेद २२६ में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। पीठ ने कहा, "कौन कह सकता है कि नियमों का पालन करने के बाद छूट दी गई है?" वकील ने जवाब देते हुए कहा कि अगर यह कोई सवाल है, तो छूट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी

चाहिए, न कि अनुच्छेद ३२ के तहत सीधे शीर्ष अदालत में। सुनवाई के दौरान, पीठ ने एक वकील की इस दलील पर आपत्ति जताई कि एक आरोपी को उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी अदालत द्वारा सही या गलत दोषी ठहराए जाने और माफी दिए जाने से पहले सजा काट लेने के बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। पीठ ने वकील से सख्ती से कहा, "यह क्या है – सही या गलत? आपको सही दोषी ठहराया गया है। वकील ने कहा कि वह सिर्फ यह कहना चाहते थे कि दोषी पहले ही १५ साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। उन्होंने कहा, "सुविधा का संतुलन दोषियों की ओर अधिक झुकता है क्योंकि वे पहले ही सजा काट चुके हैं। हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र सुधार के विचार पर आधारित है। इस स्तर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता को नहीं, बल्कि जेल में दोषियों के आचरण को देखा जाना चाहिए।" दोषियों की ओर से दलीलें बुधवार को पूरी हो गईं और अब अदालत चार अक्टूबर को अपराह दो बजे बिलकीस बानो के वकील और अन्य की जवाबी दलीलें सुनेगी। अदालत ने पूर्व में कहा था कि कुछ दोषियों को अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। दोषी रमेश रूपाभाई चंदना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि दोषियों के सुधार और पुनर्वास के लिए छूट देना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित स्थिति है तथा जब कार्यपालिका निर्णय ले चुकी है तो अब बिलकीस बानो और अन्य के इस तर्क को नहीं माना जा सकता कि जघन्य अपराध के कारण उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।शीर्ष अदालत ने १७ अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए।

एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की, पांच आतंकियों पर इनाम घोषित

नइ दिल्ली। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बुधवार को हरविंदर सिंह संधू उर्फ 'रिंदा' और लखबीर सिंह संधू उर्फ 'लांडा' सहित प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को नकद इनाम दिए जाने की घोषणा की। संघीय एजेंसी ने रिंदा और लांडा प्रत्येक के लिए १०

लाख रुपये के इनाम और परमिंदर सिंह खैरा उर्फ 'पट्टू', सतनाम सिंह उर्फ ''सतबीर सिंह'' और यादविंदर सिंह उर्फ ''यद्दा'' पर पांच लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये पांच आतंकवादी भारत की शांति व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और पंजाब में आतंक फैलाने के उद्देश्य से बीकेआई की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर दर्ज एक मामले में वांछित हैं। यह मामला इस साल की शुरुआत में दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि वांछित आतंकवादियों पर पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से और व्यापारियों व अन्य प्रमुख व्यक्तियों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के जरिये प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बीकेआई के लिए धन जुटाने के अलावा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि पांचों आतंकवादी आर्थिक लाभ का वादा करके बीकेआई के लिए नये सदस्यों को भर्ती करने में लगे हुए हैं। अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में अपने गुर्गों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया है।'' मूल रूप से महाराष्ट्र का निवासी रिंदा आतंकवादी सूची में शामिल है और बीकेआई का सदस्य है। वह पाकिस्तान में रह रहा है। वहीं, लांडा, खैरा, सतनाम और यादविंदर पंजाब के निवासी हैं। प्रवक्ता ने टेलीफोन और व्हाट्सएप नंबर साझा करते हुए कहा, ''पांच वांछित आतंकवादियों की गिरफ्तारी से जुड़ी कोई भी विशेष जानकारी नयी दिल्ली में एनआईए मुख्यालय या चंडीगढ़ में एनआईए शाखा कार्यालय के साथ साझा की जा सकती है।'' इस बीच, एनआईए ने देश में आतंकी–गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए पिछले साल दर्ज दो मामलों की जांच में वांछित ५४ व्यक्तियों की तस्वीरों के साथ दो सूची सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा कीं। एक सूची में ११ व्यक्तियों और दूसरे में ४३ व्यक्तियों का नाम शामिल है। इस सूची में गोल्डी बराड़, ल रेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और अर्शदीप सिंह गिल सहित कई वांछित गैंगस्टर शामिल हैं। एजेंसी ने मोबाइल नंबर साझा करते हुए कहा, ''यदि आपके पास इनके नाम पर या इनके सहयोगियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों/परिसंपत्तियों/व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी है, तो `पया व्हाट्सऐप पर सूचित करें।

लखनऊ के पॉश इलाके देह व्यापार का भंडाफोड़, फ्लैटलै में मिली विदेशी लड़किय

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। सुशांत सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के अलखनंदा इंकेल्व में विदेशी लड़कियों से देह व्यापार कराने का मामला सामने आया। पुलिस की छापेमारी में १० से ज्यादा विदेशी महिलाएं और पुरूष मिले हैं। पड़ोसियों की सूचना के आधार पर पुलिपु स छापा मारने पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक, अलखनंदा इंकेल्व में पड़ोसी काफी दिनों से ऐसी गतिविधियों को देख रहे थे और इसको लेकर उनमें काफी चर्चा थी। पुख्ु ता जानकारी के बाद पुलिपु स को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर सभी को दबोच लिया है। अलकनंदा एनक्लेव में विदेशी महिलाओं के सेक्स रैकेट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवतियों को देखा जा रहा है, हालांकि इन लड़कियों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की और न ही महिलाओं में पुलिस के सामने किसी तरह की कोई घबराहट दिखाई। वीडियो में पुलिपु

सकर्मी महिलाओं से अपने चेहरे को ढकने के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। पुलिस इन लड़कियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने मई के माह में गाजियाबाद के मशहूर मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। वहां से करीब १०० युवक व युवतियों को पकड़ा गया था। गाजियाबाद के पैसेफिक मॉल के स्पा सेंटर पर छापेमारी में इते बड़े पैमा पै ने पर लड़के लड़कियां पकड़े गए थे। गाजियाबाद कमिश्नरेट थाना लिंक रोड पुलिस ने छापेमारी की थी। जिसमें ६१ युवयुती और ३६ युवयुकों को पकड़ा गया था।

नशे में धुत भाजपा नेता ने दंपती से की अभद्रता तो नाराज महिला ने जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार देर रात को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता का बीच सड़क एक दंपती से अभद्रता करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो राजधानी के ठाकुरगंज के सतखंडा इलाके का बताया जा रहा है। लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि अमृत विचार नहीं करता है। इसमें कार सवार भाजपा नेता पर एक महिला व उसके पति से अभद्रता करने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि शराब के नशे में धुत भाजपा नेता की अभद्रता का वीडियो जब पीड़ित ने बनाना शुरू किया तो उन्होंने हाथापाई की। इस पर नाराज महिला ने भाजपा नेता के साथ गाली–गलौज करते हुए पिटाई कर दी। वहीं मामले में इंस्पेक्टर विकास राय का कहना है कि शिकायत नहीं मिली है। वीडियो में नजर आ रहा भाजपा नेता राजाजीपुरम वार्ड से पूर्व सभासद बताया जा रहा है। कार में पार्टी का झंडा भी लगा है। वह कार में बैठे हैं गाड़ी हटाने को लेकर उनका महिला और एक युवक से विवाद हुआ

अद्भुत किला : गढ़कुंडार का किला

अमरेन्द्र सहाय अमर

हमारा देशमें अजूबो और रहस्यों की एक लम्बी फेहरिश्त है. आजहमएक ऐसे ही किले के बारे में जानकारी देने जा रहेहैं जो रहस्यों और अजूबों से भरा है. जी हाँ यह है गढ़कुंडार का किला. यह किला जनपद झांसी से ७० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस किले को कब बनवाय गया , किसने बनवाया इसका कोई लिखित प्रमाण नही है लेकिन कहा जाता है इसका निर्माण ११ वीं सदी में हुआ था .यह१५०० से २००० साल पहले का बना बताया जाता है. यहां चंदेलो, बुंदेलोंऔर खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा है. पांच मंजिल वाले इस किले तीन मंजिल तो ऊपर है जबकि दो मंजिल जमीन के नीचे बना है. यह किला दुश्मनों को अपने पास पहुंचने नहीं देता था. दूर से विशाल दिखने वाला किला पास पहुंचते–पहुंचते आंखों से ओझल हो जाता. इसके गायब होने की पहेली को समझाना बहुत आसान है. किला असल में चारों तरफ से छोटी–छोटी पहाड़ियों से घिरा है. जैसे–जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आसपास की पहाड़ियां बड़ी दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिपता चला जाएगा. आगे चलने पर भी यह मुश्किल हल नहीं होती. तब कई रास्ते नजर आने लगते हैं, और यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि किले की ओर कौन सा रास्ता जाएगा. इसीलिए किले पर हमला करने आई दुश्मन सेनाएं गलत रास्ते पर भटक जातीं.अगर कोई किले के पास पहुंच भी जाए तो इसे जीतना आसान नहीं था. किले की ऊंची और मोटी दीवारों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था. दुश्मन के आते ही दुर्ग की रक्षा कर रही सेना परकोटे के छेदों से नीचे हमला बोल देती और दुश्मन बाल भी बांका न कर पाते. आप अगर वहां जाएं तो निगरानी के लिए बनाए गए कई बुर्ज आज भी सही सलामत मिल जाएंगे. इसे गढ़कुंडार का दुर्ग कहते हैं, जिसे चंदेल राजा यशोवर्मन ने नौवीं सदी में बनवाया था. कई पीढ़ियों तक वहां चंदेलों का शासन रहा, लेकिन सन ११८२ में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमार्दि देव को हराकर चंदेलों की राजधानी महोबा पर कब्जा कर लिया. इस जीत के फौरन बाद महोबा से कोई सवा सौ किलोमीटर दूर बना यह दुर्ग भी उनके कब्जे में आ गया. पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेतसिंह खंगार को गढकुंडार का किलेदार बना दिया. दस साल बाद ११९२ में पृथ्वीराज जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए, तब खेतसिंह ने खुद को गढ़कुंडार का राजा घोषित कर दिया. इस तरह बारहवीं सदी के आखिरी दशक में शुरू हुआ खंगारवंश का राज. इस वंश की चार पीढ़ियों ने गढ़ कुंडार पर शासन किया. इस दौरान खंगार शासकों ने नई सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं शुरू कीं, जो बुंदेलखंड के कई ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में आज भी जिंदा हैं. कहते हैं, कि खंगार राजा नारी सम्मान को लेकर बेहद सजग थे. उनके दौर में ही बेटी पूजन की शुरुआत हुई. यह प्रथा बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में तब से चली आ रही है. स्थानीय लोगों के बीच लोककथाएं और लोकगीत भी मशहूर हैं जिनसे खंगार राज का इतिहास पता चलता है. ऐसी ही दो कथाओं में खंगारवंश के अंत का पता चलता है. एक कथा के मुताबिक, सन १३४७ में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर हमला किया और खंगार राजा मानसिंह को हरा दिया.हार के फौरन बाद राजा मानसिंह की बेटी 'केसर दे' ने महल की दासियों और राज्य की कई अन्य स्त्रियों के साथ अग्नि कुंड में कूदकर जौहर कर लिया. केसर दे के बलिदान के लोकगीत इस क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं. वह विशाल कुंड आज भी किले के अंदर मौजूद है. इतिहास की पड़ताल में लगे लोगों के मुताबिक, तुगलक के बाद गढ़कुंडार बुंदेला शासकों के पास आ गया. आस पास के लोग बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पास के एक गाँव में एक बारात आईथी. बरात में आये लोग घूमते घूमते किले के बेसमेंट में चले गये . इसके बाद यह सभी बाराती रहस्यमय ढंग से गायब हो गये. उन५० ६० बारातियों का आज तक पता नहीं चला कि वे कहाँ चले गये. कुछ लोगों का मानना है इस किले में कोई गुप्त खजानाहै. इतिहासके जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोने, हीरे जवाहरातों कि कोई कमी नहीं थी इस खजाने की खोज में कई लोगों की जान जा चुकी है. इसके बाद कुछ और इस तरह की घटनाये हुई तो किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया. दरअसल यह किला भूलभुलैयाकीतरह है. अगर इसके बारे में जानकारी न हो तो अधिक अन्दर जाने पर कोई भी इस किले के अन्दर दिशा भूल सकता है।

आंगनबाड़ी के स्मार्ट फोन में फर्जीवाड़ा, उपनिदेशक दोषी

लखनऊ । वर्ष २०१६–२० में ५१ जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को १२३ करोड़ से अधिक रुपये के बांटे गए १,२३,६३८ स्मार्टफोन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जो सामने आने के बाद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग दबाए है। यह फोन राज्य पोषण मिशन से खरीदकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अ नलाइन कामकाज के लिए दिए थे। जिसकी खरीद एक उपनिदेशक ने जेम पोर्टल से सिर्फ एक फर्म को लाभ देकर कस्टम विकल्प से की थी। जबकि अन्य फर्मों द्वारा डाली गई बिड मानकों में उलझाकर बिना कारण निरस्त कर दी थी। उस समय राज्य पोषण मिशन के निदेशक (वित्त) ने जांच कराई तो नियमविरुद्ध खरीद के साथ उपनिदेशक को दोषी पाया था और तथ्य छिपाकर गलत टिप्पणी करने पर कार्रवाई की संस्तुति की थी। जिस पर शासन ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जो नहीं हुई। इधर, झांसी की एक समाजसेवी ने शासन को अवगत कराया है। वहीं, मामले पर निदेशक

सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है न ही यह मामला संज्ञान में आया है। यह भी सामने आया कि एक हैंडसेट जीएसटी समेत १० हजार रुपये तक खरीदना था। जो एक प्रतिष्ठित कंपनी से साठगांठ कर जीएसटी समेत ८ हजार रुपये का सौदा तय हुआ। लेकिन कमाई के चक्कर में पूर्व के एक उच्च अधिकारी ने केंद्र से अनुमति लेकर १८०० रुपये अलग से जीएसटी लगाकर ६,८०० रुपये के फोन खरीदे। जिसका जांच में उल्लेख नहीं किया गया। वहीं, खरीदे गए स्मार्टफोन की तकनीकी जांच भी बिना अनुभवी संस्था से कराकर पास कर दिए गए। जिलों पर चर्चा यह भी है कि जो स्मार्टफोन दिए गए वह मॉडल बंद हो गए थे। जिसकी एक साथ खरीद की गई। उनकी गुणवत्ता खराब है और क्षमता भी कम है। इसलिए ज्यादातर फोन उसी समय खराब हो गए थे। इस कारण अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकत्री सरकारी स्मार्टफोन घरों पर रखकर अपने निजी से काम कर रही हैं। इससे पहले ५४ हजार स्मार्टफोन दूसरी कंपनी के खरीदे गए थे। उसमें भी तमाम खराब निकले।

सपा सांसद डिंपलडिं यादव ने महिला आरक्षण बिल किया समर्थनर्थ, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं

नई दिल्ली। नए संसद भवन में केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। संसद के विशेष सत्र के पहले ही दिन मोदी

सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनर्जु राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस पर मैनमै पुरी पु से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इस बिल का समर्थनर्थ करतीं हूं, लेकिन हमचाहते हैं जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला को भी उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इसमें व्ठ महिलाओं को भी आरक्षण मिले। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। क्योंकि ये बिल २०२४ इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले पांच राज्यों के इलेक्शन में भी लागूनहीं हो पाएगा। वहीं सपा मुखिमु या अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के द्वारा कही गई बातों को ही दोहराया है। दरअसल पिछली बार जब यह बिल पास किया गया था तो मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण देने की मांग की थी। और बिल का विरोध किया था। इस बार अखिलेश ने भी उनकी बातों को दोहराया है। उन्होंने महिला आरक्षण में पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के लिए भी कोटा की मांग की।

एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा शराब माफिया पोषाहार सप्लाई करता था : योगी

लखनऊ। मुख्मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 'राष्ट्रीय पोषण माह' के अंतअं र्गतर्ग आज लखनऊ में १५५ करोड़ लागत के १,३५६ आंगनआं वाड़ी केंद्रों और ५० करोड़ लागत के १७१ बाल विकास परियोजना कार्यालर्या यों मां ने किया था। मुख्मु यमंत्री ने कहा कि, National Family Health Survey में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक समय उत्तर

का लोकार्पणर्प धशिलान्यास किया। इस अवसर पर २.६ लाख आंगनआं वाड़ी कार्यकर्य त्री व सहायिकाओं को यूनियू फ र्म हेतु २६ तु करोड़ धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरण अं की गई। इस मौके पर मुख्मु यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में चलाया जा रहा यह पोषण अभियान 'स्वस्थ भारत–समर्थ भारत' की नींव सु सुढ़ करता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनआं बाड़ी कार्यकर्यत्रियों के लिए अपने संबोधन में कहा था कि ये वही काम करती हैं, जो कभी यशोदा प्रदेश के अंदरअं, प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया पोषाहार सप्लाई करता था। हमारी सरकार ने एक नया मैकेमै केनिज्म बनाया कि जिसके माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहमू आंगनआं बाड़ी केंद्रों तक आज पोषाहार पहुंचा रही हैं। इसी का नतीजा है नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। आंकआं ड़े देखें तो २०१५–२०१६ के सापेक्ष प्रदेश में २०१६–२०२० में एनीमिया में ५.१ प्रतिशत, बौनापन में ६.६ प्रतिशत, अल्प वजन में ७.४ प्रतिशत और सूखापन में ०.६ प्रतिशत का सुधार हुआ है।

उर्वरकों की जांच को बनी टीमें, 25 तक मांगी रिपोर्ट

लखनऊ। रबी फसलों के लिए उपलब्ध कराई गई उर्वरकों की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी विकास खंड पर टीमें गठित कर दी हैं। जो छापेमारी कर २५ सितंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी। रबी के दौरान उर्वरकों में खासकार डीएपी की किल्लत न रहे इसके लिए अभी से सतर्कता बरती जा रही है। शासन ने सभी जिलों को उपलब्ध ा कराई गई डीएपी समेत अन्य उर्वरकों की जांच के निर्देश दिए हैं। जिसके क्रम में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने जिले में आठ विकास खंड पर एक–एक टीम बनाई है। जो सभी उर्वरक के

फुटकर व थोक बिक्री केंद्र, उनके गोदाम व बफर में स्टॉक व बिक्री की पीओएसप मशीन से मिलान कर जांच करेंगे। जिला ृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि २५ सितंबर तक जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।

सिटी मोंटेसरी स्कूल में बच्चे की मौत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। कक्षा ६ में पढ़ने वाले एक छात्र की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। छात्र का नाम आतिफ सिद्दीकी बताया जा रहा है। आतिफ सीएमएस में कक्षा ६ का छात्र था। दरअसल, अलीगंज के सेक्टर ओ में स्थित अलीगंज ब्रांच में कक्षा ६ के छात्र की उस समय हालत बिगड़ गई, जब वह क्लास में पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान अचानक आतिफ सिद्दीकी बेहोश होकर गिर पड़ा। आतिफ के गिरते ही क्लास रूप में अफरा तफरी मच गई। आनन– फानन में शिक्षकों ने आतिफ को अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान आतिफ ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। स्कूल के टीचर नदीम के मुताबिक वह क्लास में कमेस्ट्री पढ़ा रहे थे। इस दौरान ही आतिफ बेहोश हुआ। बच्चे को बेहोश होता देख उसको लेकर हमलोग पास के नर्सिंगहोम में पहुंचे। जहां पर मौजूद चिकित्सकों ने केजीएमयू के लॉरी ले जाने की सलाह दी। हालांकि इस दौरान डॉक्टर ने यह भी कहा कि बच्चे की पल्स नहीं चल रही है।

एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते लेखपाल को रंगेहाथ दबोचा

लखनऊ। लखनऊ सदर तहसील में सोमवार को एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को १५ हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें सड़क पर हंगामा कर रहे लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम घसीटते हुए ले जा रही है। रायबरेली से ट्रांसफर होकर कुछ दिन पहले ही तहसील सदर आये लेखपाल अविनाश ओझा को सोमवार दोपहर एंटी करप्शन की टीम ने एक व्यक्ति से १५ हजार रुपये लेते रंगे हाथ दबोचा।

जिस व्यक्ति से लेखपाल रुपये ले रहे हैं। उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन के अफसरों से की थी। इसी के आधार पर टीम के सदस्यों ने शिकायतकर्ता को रुपये देने के लिए लेखपाल के पास भेजा। इस दौरान जैसे ही लेखपाल ने शिकायतकर्ता से रुपये लिये आसपास मौजूद एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उसे दबोच लिया। इस घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि लेखपाल बीच सड़क पर हंगामा कर रहा है और टीम उसे घसीटते हुए ले जा रही है। लेखपाल खुद को बेकसूर बताते हुए शोर मचा रहा है। इस दौरान तहसील के कई कर्मी भी आसपास मौजूद दिख रहे हैं। लेखपाल की गिरफ्तारी की सूचना फैलते ही सदर तहसील के कर्मचारी भी बाहर एकत्र हो गए। अविनाश ओझा खुद को निर्दोष बताते हुए टीम के साथ न जाने पर अड़ गए। तब टीम ने बल का प्रयोग करते हुए उनके जमीन पर लेटने पर उठाकर ले गई। एंटी करप्शन टीम ने बताया कि अविनाश पर एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। केस दर्ज होने के बाद ही गिरफ्तारी की जानकारी दी जायगी। गोमतीनगर के खरगापुर, कौशलपुरी क लोनी के रहने वाले अमन त्रिपाठी ने हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन किया था। सभी कागजात दुरुस्त होने के बाद भी प्रमाण–पत्र नहीं बन पा रहा था। लेखपाल अविनाश चंद्र ओझा से संपर्ककिया तो उन्होंने १५ हजार रुपये घूस मांगी। मैने इसकी शिकायत एंटी करप्शन में की थी। टीम के सदस्यों ने लेखपाल के पास जाने को कहा। मुझसे लेखपाल ने जैसे ही रुपये लिये टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। लेखपाल अविनाश ओझा का तबादला हाल में रायबरेली से लखनऊ हुआ था। मामले को लेकर एडीएम प्रशासन डॉ. शुभी सिंह का कहना है कि अभी एंटी करप्शन की तरफ से लेखपाल के संबंध में कोई पत्र नहीं आया है। पत्र मिलने पर लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

लाठीचार्ज के विरोध में हापुड़ के वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी

लखनऊ। पिछले अगस्त महीने में हापुड़ में वकीलों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ और हापुड़ में वकील बुधवार को हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने लखनऊ में राज्य के मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बाद १४ सितंबर को हड़ताल वापस ले ली थी। हालांकि, लखनऊ बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया। लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण ने बताया कि लखनऊ बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें वकीलों ने २१ सितंबर तक न्यायिक कार्य से दूर रहने और उस दिन भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हापुड़ लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई और इससे वकीलों में आक्रोश है। नारायण ने कहा, ष्हम हापुड़ के वकीलों के साथ हैं। उनकी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।ष् उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा हड़ताल वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने १५ सितंबर को हापुड़ के अपर पुलिस अध ीक्षक सहित तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक (हापुड़) अभिषेक वर्मा ने बताया था कि सरकार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मुकेश चंद्र वर्मा, क्षेत्राधि ाकारी (शहर) अशोक कुमार सिसोदिया और हापुड नगर के थाना प्रभारी सतेंद्र प्रकाश सिंह को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वकील हापुड में कथित पुलिस लाठीचार्ज को लेकर ३० अगस्त से हड़ताल पर थे। हापुड़ बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा के मुताबिक, वकीलों ने मांग की है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। गोरखपुर से मिली जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पांडेय ने कहा कि गोरखपुर में वकील मंगलवार को हड़ताल पर थे लेकिन बुध ावार से उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। गोरखपुर में वकील ३० अगस्त से हड़ताल पर थे। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग के समर्थन में वकील हर शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर महानिदेशक (अभियोजन) इसके सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई पर विचार के लिए अवगत कराएगी। गौरतलब है कि गत २६ अगस्त को हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद राज्य भर के सभी जिला बार संगठनों द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है।

महिला आरक्षण विधेयक एक 'युगांतरकारी कदम' : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक 'युगांतरकारी कदम' करार दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच श्एक्सश् पर कहा, ष्भारत का महान लोकतंत्र आज सच्चे अर्थों में गौरवभूषित हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आज लोक सभा में प्रस्तुत किया गया 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। समूची मातृशक्ति को हार्दिक बधाई!ष् उन्होंने इसी पोस्ट में कहा, 'देश की आधी आबादी को उनका हक देने तथा भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत व सहभागी बनाने वाला यह कालजयी निर्णय

'विकसित भारतश् के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा।' आदित्यनाथ ने एक अन्य पोस्ट में नए संसद भवन का जिक्र करते हुए कहा, '१४० करोड़ भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता श्नया संसद भवनश् मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ ही हमारे सशक्त एवं स्वर्णिम भविष्य का शाश्वत प्रतीक बनेगा।' उन्होंने कहा, 'मुझे पूर्ण विश्वास है, यह संसद भवन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की अविराम यात्रा को और गति प्रदान करेगा। देश वासियों को हार्दिक बधाई! 'केंद्र सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।

अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्य समिति गठित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन का फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर महानिदेशक (अभियोजन) इसके सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराएगी। पिछली २६ अगस्त को हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के बाद राज्य भर के सभी जिला बार संगठनों द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है।

गोंडा में लावारिस मिले दो नवजात, एक की हुई मौत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला मुख्यालय पर मंगलवार को अलग अलग जगहों से दो लावारिस नवजात शिशु बरामद हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय के सर्जिकल वार्ड के शौचालय में मंगलवार को सफाई कर्मचारी को खून से लथपथ एक नवजात बालिका बरामद हुई, जिसका गर्भनाल भी जुड़ा हुआ था। अधिकारी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट आजाद ने उसे जिला महिला चिकित्सालय के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार हो रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ड. वीके गुप्ता ने बताया कि बच्ची अब खतरे से बाहर तथा स्वस्थ है। पुलिस ने बताया कि दूसरी नवजात बालिका सिविल लाइंस क्षेत्र के विष्णुपुरी मोहल्ले में स्थित एक नर्सिंग होम के पास कूड़े के ढेर में बरामद हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली नगर के थाना प्रभारी निरीक्षक संजय गुप्ता ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मामले अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की एक जिला अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के दो मामलों की सुनवाई मौजूदा न्यायाधीश से किसी अन्य न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि न्यायाधीश की कड़ी टिप्पणी यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकती कि मामले की सुनवाई पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी। जिला न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने जैन की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान कुछ आदेश अभियोजन के पक्ष में हो सकते हैं और कुछ बचाव पक्ष के अनुकूल, लेकिन इस तरह के आदेश को संबंधित न्यायाधीश को पक्षपाती कहने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के दो मामले हैं जो उन्होंने १४ फरवरी २०१५ को दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेनेऔर ३१ मई २०१७ के बीच कथित तौर पर अर्जित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है जबकि प्रवर्तन निदेशालय मामले से जुड़े धनशोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। जिला न्यायाधीश ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि अदालत दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका दे रही है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। न्यायाधीश ने कहा, "मेरा विचार है कि आवेदनकर्ता द्वारा पक्षपात की जताई गई आशंका में कोई दम या तथ्य नहीं है।" जैन ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित कर दी जाए क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे मौजूदा न्यायाधीश ने "पहले ही मामले का फैसला कर लिया है।" उन्होंने दावा किया कि उन्हें "आशंका है कि मौजूदा समय में जो न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं उनके समक्ष उचित सुनवाई नहीं होगी।" जिला न्यायाधीश ने कहा कि जब पक्षपात की आशंका से मामलों का स्थानांतरण एक अदालत से दूसरी अदालत में किया जाने लगा तो इसके बड़े दुष्प्रभाव होंगे।

शिव शक्ति प्वाइंट पर सूर्योदय, फिर जागने वाले हैं विक्रम और रोवर प्रज्ञान?

नई दिल्ली। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर सुबह होने वाली है। इसके साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने की तैयारी हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने चंद्रयान-३ मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ फिर से संचार स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। चंद्र रात्रि के कारण चंद्र जोड़ी पिछले १५ दिनों से स्लीप मोड में है, लेकिन शिव शक्ति प्वाइंट पर सूर्य के प्रकाश के आगमन के साथ उनकी परिचालन स्थितियों में सुधार होने की उम्मीद है। इसरो ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रूवीय क्षेत्र में चंद्रयान-३ लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय हो चुका है और वे बैटरी के रिचार्ज होने का इंतजार कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें विक्रम और प्रज्ञान के साथ फिर से संचार स्थापित होने की उम्मीद है। मिशन के लिए सूर्योदय एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह लैंडर और रोवर को कार्य करने के लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करेगा। इसरो ने कहा है कि वे २२ सितंबर को संचार प्रयास शुरू करने से पहले तापमान के एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ने का इंतजार करेंगे। १४ जुलाई, २०२३ को लॉन्च किया गया चंद्रयान-३ मिशन पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इसने भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बना दिया। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य इस वैज्ञानिक रूप से पेचीदा क्षेत्र का पता लगाना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जमा हुआ पानी मौजूद है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर २३ अगस्त को उतरने के बाद से विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रमा के आयनमंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व को मापा है और चंद्रमा की सतह के तापमान की रीडिंग ली है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की पहली छवि भी खींची। हालाँकि, चाँद की रात में परिचालन रुक गया क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की बैटरियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं थीं कि वे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपने सिस्टम को चालू रख सकें। चंद्रमा की सुबह के साथ, इसरो को उम्मीद है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक्स उस ठंडी रात में जीवित रहने में सक्षम हैं तो मिशन अपने अभूतपूर्व अन्वेषण को फिर से शुरू कर सकता है।

खेल-खेल में गले में फंदा लगने से बच्चे की मौत, माँ ने किया ये खुलासा

लखनऊ। कोतवाली उरई क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में एक बच्चे की खेल-खेल में गले में फंदा लगने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोतवाली उरई की काशीराम कॉलोनी के थाना प्रभारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि रविवार को खेमजंद का बेटा जयेश (१३) अपने घर में अपनी छोटी बहन महक एवं आस्था के साथ खेल रहा था। उन्होंने बताया कि खेल खेल में जयेश ने आंखों में पट्टी बांधकर एक रस्सी का फंदा भी अपने गले में लगा लिया और रस्सी को खिड़की से बांध दिया और छोटी सी मेज पर बैठ गया। तभी अचानक मेज में किसी का धक्का लग गया और मेज नीचे गिर गई जिससे बच्चे के गले में लगा फंदा कस गया और उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी आरिफ ने बताया कि बच्चे की मां दृष्टिबाधित है और मां का कहना है कि अगर उसे दिखाई देता तो उसके बेटे की मृत्यु नहीं होती।

खराब सड़क को लेकर सीएम योगी की नाराजगी के बाद सुपरवाइजर निलंबित

लखनऊ। मंगलवार को देवा रोड पर एक होटल में आयोजित समन्वय बैठक में शामिल होने गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मटियारी चौराहे पर सड़क के गड्ढों और जलभराव को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इसको लेकर अधिकारियों ने एक्शन लिया है। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने लापरवाही करने पर नगर निगम जोन सात में तैनात अवर अभियंता अरुण मेहता और सफाई निरीक्षक देवेंद्र वर्मा खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की है और सुपरवाइजर अवधेश को निलंबित कर दिया है। जोनल अधिकारी मनोज यादव को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। नगर आयुक्त के अनुसार कुछ और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।

तीन आईपीएस अफसरों के तबादले, केसी गोस्वामी को मिली हरदोई की कमान

लखनऊ। यूपी में ३ आईपीएस अफसरों के तबादले किये गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरदोई में केशव चंद्र गोस्वामी को एसपी के पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले हरदोई के एसपी रहे राजेश द्विवेदी को रामपुर का एसपी बनाया गया है। जबकि रामपुर एसपी अशोक कुमार को हटाया गया है। इसके अलावा अशोक कुमार को एसपी सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर भेजा गया है।

महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी 'यमराज' आपका इंतजार कर रहे हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगर राज्य में कोई महिला उत्पीड़न जैसा अपराध करेगा तो श्यमराजश उसका इंतजार कर रहे होंगे।यह टिप्पणी तब आई है जब एक छात्रा की जान चली गई जब दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने छेड़छाड़ के प्रयास में उसका श्दुपट्टाश खींच लिया, जिसके कारण वह साइकिल से गिर गई और अंबेडकरनगर में एक अन्य मोटरसाइकिल चालक ने उसे कुचल दिया। घटना शुक्रवार को हुई और तीनों आरोपियों को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने दावा किया कि रविवार को हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान दो आरोपियों को गोली लगी, जबकि एक का पैर फ्रैक्चर हो गया। जिले में ३४३ करोड़ रुपये की ७६ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद यहां एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अगर कोई राज्य में महिलाओं को परेशान करने जैसा अपराध करता है, तो मृत्यु के देवता श्यमराजश उसका इंतजार कर रहे होंगे। आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा अक्सर राज्य में कानून–व्यवस्था को संभालने में आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियों में से

एक बताती रही है। सीसीटीवी फुटेज में, पीड़िता, जो ११वीं कक्षा की छात्रा थी, और एक अन्य लड़की को अपनी साइकिल पर चलते हुए देखा जाता है, तभी एक तेज रफ्तार बाइक पीछे से उसके पास आती है और उसके पास से गुजरते समय पीछे बैठा व्यक्ति उसका दुपट्टा खींच लेता है। लड़की अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाती है और पीछे से आ रहा दूसरा मोटर चालक उसे कुचल देता है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुपट्टा खींचने वाले सहबाज और उसके भाई अरबाज के रूप में हुई। तीसरे आरोपी फैसल ने लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी. अधिकारियों ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी भाइयों और फैसल के बीच कोई संबंध है या नहीं। अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा ने रविवार को बताया, ष्तीनों आरोपियों को रविवार को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तीनों वाहन से कूद गए। उन्होंने पुलिस राइफल भी छीन ली और हमारी टीम पर गोलीबारी की।ष उन्होंने कहा, ष्जवाबी गोलीबारी में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे का पैर फ्रैक्चर हो गया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।ष आरोपियों पर आईपीसी की धारा ३०२ (हत्या) और ३५४ (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला) के साथ–साथ च्व्ब्ै (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने अनिल कपूर के नाम, तस्वीर, आवाज का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अनिल कपूर के मशहूर सूत्रवाक्य ''झकास'' समेत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का व्यवसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता द्वारा कई वेबसाइट और मंचों के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया। कपूर ने व्यवसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों के अनधिंत शोषण का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया था। अदालत के आदेश के बाद कपूर ने एक बयान में कहा, ''मेरा इरादा किसी की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करना या किसी को दंडित करना नहीं है। मेरा व्यक्तित्व, मेरे द्वारा जीवन भर किया गया काम है और मैंने इसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है।इस मुकदमे के माध्यम से, मैं अपने व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहा हूं।'' कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और मंच विभिन्न गतिविधियों के जरिये वादी के व्यक्तित्व के खूबियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने प्रेरक वक्ता के रूप में अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करके सामान की अनधिंत बिक्री और शुल्क वसूलने, उनकी तस्वीर के साथ अपमानजनक तरीके से छेड़छाड़ करने और जाली अ टोग्राफ तथा ''झकास'' सूत्रवाक्य वाली तस्वीरें बेचने का उल्लेख किया। याचिका में कपूर के नाम, आवाज, तस्वीर, उनके बोलने के अंदाज और हावभाव के संबंध में उनके व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित है, लेकिन जब यह ''सीमा पार करती है''

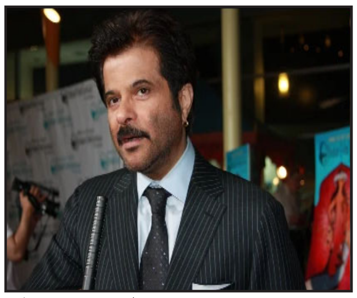

और किसी के व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों को खतरे में डालती है, तो यह गैरकानूनी हो जाती है। अदालत ने कहा, ''वादी के नाम, आवाज, संवाद और तस्वीरों का अवैध तरीके से और व्यवसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के ऐसे दुरुपयोग पर आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती।'' उसने कहा, ''प्रतिवादी संख्या एक से १६ तक को व्यवसायिक फायदे या किसी और उद्देश्य से वादी अनिल कूपर के नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से रोका जाता है।'' उच्च न्यायालय ने अन्य अज्ञात लोगों को आपत्तिजनक लिंक प्रसारित करने से भी रोक दिया। उसने संबंधित प्राधिकारी को इन आपत्तिजनक मंचों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ''व्यक्ति को ख्याति के साथ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं'' और यह मामला दिखाता है कि ''प्रतिष्ठा एवं ख्याति नुकसान में बदल सकती है'', जिससे प्रचार का उसका अधिकार प्रभावित हो सकता है।

शाहरुख खान से पहली मुलाकात में कंफ्यूज हो गए थे जवान के डायरेक्टर एटली, बताई ये वजह

मुंबई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जानेमाने निर्देशक एटली,शाहरुख खान से पहली मुलाकात में कंफ्यूज हो गए थे। एटली के निर्देशन में बनी शाहरुख खान की जवान ०७ सितंबर को प्रदर्शित हुयी थी। भारत में जवान का कुल कारोबार ५०० करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। एटली ने बताया कि जब वह शाहरुख से पहली बार मिले तो शाहरुख सर ने मुझसे कहा कि मैं 'एटली फिल्म' करना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा, 'सर, 'एटली फिल्म' क्या है?' मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूं, जिसमें एक मास डायरेक्टर के रूप में आपके सिग्नेचर हों। 'मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे शाहरुख सर, नयनतारा मैम, विजय सेतुपति, दीपिका मैम से लेकर ऐसी अद्भुत टीम मिली, उन्होंने मुझे मेरी सीमा तक पहुंचाया और मुझे बेस्ट दिया। एटली ने

बताया,' मुझे मेरे परिवार से बहुत समर्थन मिला, मेरी पत्नी प्रिया मेरी रीढ़ हैं। और, दूसरे मिस्टर खान थे, उन्होंने मुझे इस फिल्म के निर्माण के दौरान पिछले ४ वर्षों में एक टीम के रूप में सामने आई सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत दी।

अमिताभ बच्चन का गाना सारा जमाना को किया जाएगा रिक्रिएट, आइकोनिक सॉंग पर नाचेंगें टाइगर

मुंबई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना के गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना को फिल्म गणपत के लिए रिक्रिएट किया जाएगा। वर्ष १९८१ में प्रदर्शित फिल्म याराना का गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। इस गाने को इसकी कंपोजीशन के साथ ही अमिताभ बच्चन के लाइट बल्ब लगे आउटफिट के लिए भी याद किया जाता है। बताया जा रहा है कि सारा जमाना हसीनों का दीवाना गाने को टाइगर श्रॉफ–कृति सैनन की फिल्म गणपत के लिए रिक्रिएट किया जाएगा। फिल्म के प्लॉट में एक जरूरी मोड़ पर इस गाने का इस्तेमाल किया जाएगा। गुड कंपनी के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और विकास बहल द्वारा निर्देशित गणपथ–राइज ऑफ द हीरो का निर्माण वाशु

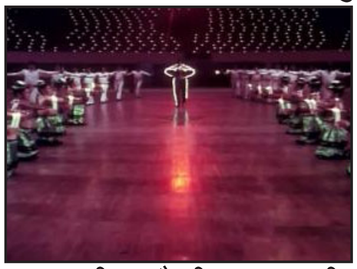

भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख और विकास बहल ने गया है। यह फिल्म २० अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
lt; ckt ib
lhrkiqj
eks-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lqjs'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
eks-09386075289
मो० अरशद
C;wjks phQ
eÅ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक